बलकार सिंह

बनाम

हरियाणा राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 606/2008)

नवंबर 17,2014

[फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला और अभय मनोहर सप्रे, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860-एस. एस.1208 और 302 आर/डब्ल्यू एस.34 - हत्या-14 अभियुक्त-षड्यंत्र के आरोप-अपराध के लिए ए-10 का दोषसिद्धि सी.120B और 302 एस 34 के साथ पढ़े जाने वाले ए-1 से ए-4-परीक्षण निचली अदालत के साथ-साथ उच्च निचली अदालत ने ए-10 को सुनियोजित साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया-जिसे चुनौती दी गई-आयोजितःषड्यंत्र के सिद्धांत का समर्थन करने के लिए सामग्री या साक्ष्य के रूप में या अन्यथा बुनियादी तत्वों की पूरी तरह से कमी थी-यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं कि ए-10 ने ए-1 से ए-4 के साथ साजिश रची थी-दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष का विशिष्ट मामला यह था कि ए-14 के इशारे पर, मुख्य साजिशकर्ता, ए-10 ने योजना को निष्पादित किया-हालाँकि, चूंकि ए-14 ने पूरे मामले में कोई भूमिका नहीं निभाई थी, इसलिए साजिश के सिद्धांत के लिए अकेले ए-10 को पिन करने की कोई गुंजाइश ई नहीं थी-तथ्यों पर, यहां तक कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय के निष्कर्षों के अनुसार, ए-5 से ए-9 और ए-11 से ए-14 के खिलाफ लगाए गए साजिश के ए/लीगेशन को खारिज कर दिया गया था-जहां तक ए-1 से ए-4 और ए-10 का संबंध था, नहीं। 120बी भा.दं.सं. सी. को ए 10 के खिलाफ पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था, अकेले उस पर आरोप नहीं लगाया जा सकता था और उस आरोप और इसके परिणामस्वरूप अन्य आरोपों का दोषी नहीं पाया जा सकता था। 302 एस के साथ पढ़ें।

34 आई. पी. सी.-ए-10 के खिलाफ यू/एस 120B, के तहत साजिश का आरोप लगाया गया। भा.दं.सं. सी.पी. सी. और एस. 34,के तहत अगला आरोप। एस 302 के साथ पढ़ें। निर्णायक रूप से साबित नहीं हुआ-ए-10 पर लगाए गए दोषसिद्धि और सजा को तदनुसार अलग कर दिया गया।

साक्ष्य-परिवेशीय साक्ष्य-परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर लगाए जाने वाले दोषसिद्धि से संबंधित सिद्धांत, निकाले गए।

शरद बर्धीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 सेक 116:1985 (1) एस. सी. आर. 88; अरविंद कुमार अनुपलाल पोद्दार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2012) 11 एस. सी. सी. 172; 2012 (12) एस. सी. आर. 299 शांति देवी बनाम शंकर लाल बनाम राजस्थान राज्य (2012) 12 एस. सी. सी. 158:2012 (9) एस. सी. आर. 226-संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

| | | |
|---|---|---|
| 1985 (1) एस. सी. आर. 88 | संदर्भित | पैरा 7 |
| 2012 (12) एस. सी. आर. 299 | संदर्भित | पैरा 8 |
| 2012 (9) एस. सी. आर. 226 | संदर्भित | पैरा 8 |

आपराधिक अधिकार क्षेत्र न्यायनिर्णयःकी दाण्डिक अपीलीय सं 606/ 2008

हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के दाण्डिक अपीलीय सं 293-डी. बी./1997 के निर्णय और आदेश दिनांक 25.05.2007 से।

सुशील कुमार, सीनियर अधिवक्ता संजय जैन अधिवक्ता अपीलार्थी के लिए।

मधुरिमा तातिया, सैयद तनवीर अहमद और मोहम्मद खैराती (बी. कृष्ण प्रसाद के लिए) अधिवक्ता उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला द्वारा दिया गया था ।

1. वर्तमान अपील को ए-1 से ए-4 द्वारा प्राथमिकता दी गई थी जिसमें ए-10 अपीलकर्ता है जिसे 2010 की दाण्डिक अपीलीय सं.1005,2010 की 992,2010 की 986 और एसएलपी (सीआरएल)सं270/2009 के साथ सूचीबद्ध किया गया था। उपरोक्त सभी अपीलों पर एक साथ सुनवाई की गई। अपीलकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुशील कुमार ने कहा कि ए-1 से ए-4 तक की सजा पूरी होने के बाद उनकी अपीलों में कुछ भी नहीं बचा और इसलिए उक्त चार अपीलों को निष्फल होने के कारण खारिज कर दिया गया।अतः ए-10 द्वारा दायर वर्तमान अपील पर सुनवाई की गई। ए-10 को भारतीय दंड संहिता (इसके बाद 'आई. पी. सी.' के रूप में संदर्भित) की खंड 120 बी के तहत अपराधों के लिए ए-1 से ए-4 के साथ साजिश में अंबाला के सतिंदर सेखों की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था।

2. जिन संक्षिप्त तथ्यों को बताया जाना आवश्यक है, वे यह हैं कि मृतक एक पेट्रोल पंप का मालिक था जिसे उसने 08.03.1992 पर शुरू किया था। यह घटना 16.07.1994 को सुबह 11.30 पर हुई। उस दिन मृतक अपने भाई हरिंदर सिंह पूर्वाह्नखों (पी. डब्ल्यू.-22) और सुरजीत सिंह (पी. डब्ल्यू.-25) नाम के एक कर्मचारी के साथ ढिल्लों सर्विस स्टेशन, एक अन्य पेट्रोल पंप गया था। उन्होंने पंजीकरण सं. HNA 7878 वाली मारुति कार में यात्रा की। मृतक उक्त पेट्रोल पंप पर गया, जिसका मालिक रविंदर सिंह ढिल्लों (पीडब्लू-23) था, जो वहां से खरीदे गए मोबिल तेल के लिए भुगतान करने के लिए घटना का चश्मदीद गवाह था।मृतक अपने भाई के साथ पेट्रोल पंप के केबिन के अंदर बैठा था और पीडब्लू-23 से बात कर रहा था। ए-1 से ए-

4 यानी गुरदेव सिंह, सोहन सिंह, नायब सिंह और वकील सिंह स्वर्ण सिंह (पीडब्लू-36) के स्वामित्व वाले नकली पंजीकरण सं. CHO1-J-9846 (वास्तविक पंजीकरण सं.HR-34-0010) वाले मारुति 800 में उक्त पेट्रोल पंप पर गए। उनमें से दो ने पेट्रोल माँगा और जब उन्हें बताया गया कि पेट्रोल खत्म हो गया है, तो उक्त दो व्यक्ति कार्यालय के केबिन के अंदर गए और कुछ शीतलक माँगा। जब पीडब्लू-23 सेल्समैन रजनीश कुमार दत्ता (पीडब्लू-24) से शीतलक देने का अनुरोध कर रहा था, तो चाकू से लैस दो घुसपैठियों में से एक ने मृतक को चाकू मारना शुरू कर दिया, जबकि दूसरे ने मृतक को पीछे से पकड़ लिया। इस बीच, कार में सवार दो अन्य लोग, जिनमें से एक बंदूक से लैस था और दूसरा डंडा से लैस था, भी कार्यालय के केबिन में घुस गए और बंदूक पकड़े हुए व्यक्ति ने कोई अलार्म नहीं बजाने की धमकी दी और उनमें से एक ने टिप्पणी की कि मृतक को पेट्रोल पंप चलाने के लिए सबक सिखाया गया था।मृतक गिर गया और चारों हमलावर उस कार में भाग गए जिसमें वे आए थे।इस प्रकार हत्या को पीडब्लू-22,23,24 और 25 ने देखा।भा.दं.सं. सी. की खंड 34 के साथ पठित अपराध के लिए उसी दिन दोपहर 2 बजे किसी भी नाम का उल्लेख किए बिना प्राथमिकी आर. दर्ज की गई थी।

3. 22.07.1994 पर, A-1 से A-4 ने आत्मसमर्पण कर दिया। 24.07.1994 को इंस्पेक्टर रिशाल सिंह (पीडब्लू-53) ने ए-5, ए-6, ए-7 और ए-8 यानी बलकार सिंह गुर्जर, गुलजार सिंह, मंगल सिंह और जसबिर सिंह को गिरफ्तार किया। 27.07.1994 पर, अपीलकर्ता (ए-10) और कमलजीत सिंह (ए-11) को पीडब्लू-53 द्वारा गिरफ्तार किया गया था। 23.07.1994 पर, दलबीर सिंह (ए-9) ने आत्मसमर्पण कर दिया। 29. 07.1994 पर फकीर चंद (ए-12) को गिरफ्तार किया गया और 8.8.1994 पर मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (इसके बाद 'सी. बी. आई.' के रूप में संदर्भित) को सौंप दिया गया। सी. बी. आई. ने 09.08.1994 पर अपनी जाँच शुरू की। इसके बाद, दर्शन सिंह (ए-13)

को 15.08.1994 पर गिरफ्तार कर लिया गया। 22.10.1994 पर निर्मल सिंह (ए-14) ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस बीच, 15.10.1994 पर आरोप-पत्र दाखिल किया गया।कुल मिलाकर 14 अभियुक्तों पर भा.दं.सं. सी. की खंड 120बी, खंड 34 के साथ पठित खंड 302 के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया था। कुछ अभियुक्तों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम, 1959 के साथ-साथ भा.दं.सं. सी. की खंड 201 के तहत अपराध थे। निचली अदालत ने ए-1 से ए-4, ए-10 और ए-11 को भा.दं.सं. सी. की खंड 120बी और खंड 34 के साथ पढ़े जाने वाले अपराधों के लिए दोषी ठहराया। ए-14 सहित बाकी अभियुक्तों को भा.दं.सं. सी. की खंड 120बी के साथ-साथ खंड 34 के साथ पठित खंड 302 के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया। ए-1 से ए-4, ए-10 और ए-11 ने 1997 की दाण्डिक अपीलीय डी. बी., 1997 की 283 डी. बी. और 1997 की 295 डी. बी. में उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलों को प्राथमिकता दी।ए-10 द्वारा दायर अपील 1997 की दाण्डिक अपीलीय सं.293 डीबी थी और ए-11 द्वारा दायर अपील 1997 की दाण्डिक अपीलीय सं.304 डीबी थी।राज्य ने सी. बी. आई. द्वारा से ए-14 और पांच अन्य को दोषमुक्ति जाने के खिलाफ 1997 की दाण्डिक अपीलीय डी. बी. ए. दायर की। ए-14 और तेरह अन्य को दोषमुक्ति जाने के खिलाफ शिकायतकर्ता पीडब्लू-22 द्वारा 1997 का आपराधिक संशोधन सं.575 दायर किया गया था।

4. विवादित निर्णय द्वारा, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने अपीलार्थी की 1997 की दाण्डिक अपीलीय डी. बी. होने के साथ-साथ ए-1 से ए-4 द्वारा की गई अपीलों को खारिज कर दिया। ए-11 द्वारा दायर अपील, अर्थात् 1997 की दाण्डिक अपीलीय डी. बी. को अनुमति दी गई और उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।शिकायतकर्ता द्वारा पसंद किया गया संशोधन 1997 का आपराधिक संशोधन है जिसे भी खारिज कर दिया गया था।1 997 की दाण्डिक अपीलीय डी. बी. ए. में ए-5

और अन्य को दोषमुक्ति जाने के खिलाफ सी. बी. आई. द्वारा दायर अपील को भी खारिज कर दिया गया था।

5. हमने अपीलकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुशील कुमार और सी. बी. आई. की विद्वान अधिवक्ता सुश्री मधुरिमा तातिया को सुना।

6. वर्तमान अपील में, हम केवल ए-10 के बारे में चिंतित हैं जिसे ए-1 से ए-4 के साथ खंड 120बी और खंड 34 के साथ पठित खंड 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। ए-10 के खिलाफ पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था। इसलिए, अपीलकर्ता के मामले और संबंधित वकील की दलीलों के बारे में चर्चा में प्रवेश करने से पहले, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर लगाए जाने वाले किसी भी दोषसिद्धि से संबंधित सिद्धांतों को संक्षेप में बताना सार्थक होगा, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में बार-बार निर्धारित किया गया है। इस तरह के परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अपीलकर्ता को दोषी ठहराते समय निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा किए गए दृष्टिकोण की सराहना आदेशने के लिए इन सिद्धांतों को निकालना आवश्यक होगा।

7. सबसे पहले, हम शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य-(1984) 4 एस. सी. सी. 116 में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के पहले के एक निर्णय का संदर्भ दे सकते हैं, जिसमें इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने किसी अभियुक्त के खिलाफ मामले को पूरी तरह से स्थापित कहने से पहले पूरी करने की शर्तों को निर्धारित किया है। पैराग्राफ 153 में भी यही बताया गया है, जो इस प्रकार हैः

> "153. इस निर्णय के गहन विश्लेषण से पता चलेगा कि किसी अभियुक्त के खिलाफ मामले को पूरी तरह से स्थापित होने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिएः

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।

यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया कि संबंधित परिस्थितियाँ "होनी चाहिए या होनी चाहिए" और "नहीं" स्थापित की जा सकती हैं।"साबित किया जा सकता है" और "होना चाहिए या साबित किया जाना चाहिए" के बीच न केवल एक व्याकरणिक बल्कि एक कानूनी अंतर है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य में अभिनिर्धारित किया गया था जहां निम्नलिखित टिप्पणियां की गई थीं:[एससीसी पैरा 19,पी. 807:एस. सी. सी. (सी. आर. आई) पी.1047]

"निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले दोषी होना चाहिए और न कि केवल दोषी होना चाहिए और 'हो सकता है' और 'होना चाहिए' के बीच की मानसिक दूरी लंबी है और कुछ निष्कर्षों से अस्पष्ट अनुमानों को विभाजित करती है।"

(2) इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात, वे किसी अन्य परिकल्पना पर समझाने योग्य नहीं होने चाहिए सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है,

(3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए,

(4) उन्हें साबित होने के लिए एक को छोड़कर हर संभव परिकल्पना को बाहर करना चाहिए, और

(5) साक्ष्य की एक श्रृंखला इतनी पूरी होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होना चाहिए।" (जोर दिया गया)

8. हाल के दिनों में, उपरोक्त सिद्धांतों का पालन किया गया है और इस न्यायालय द्वारा अरविंद कुमार अनुपलाल पोद्दार बनाम महाराष्ट्र राज्य-(2012) 11 एस. सी. सी. 172 और शांति देवी बनाम शंकर लाल बनाम राजस्थान राज्य-(2012) 12 एस. सी. सी. 158 में बताए गए निर्णयों में लागू किया गया है। शांति देवी (ऊपर) में प्रासंगिक सिद्धांतों को पैराग्राफ 10 और 10.1 से 10.4 तक निकाला जा सकता है जो इस प्रकार हैंः

"10. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और हमारे सामने आरोपित निर्णय और अन्य भौतिक दस्तावेजों पर गंभीरता से विचार आदेशने के बाद, क्योंकि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है, हम इस न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में निर्धारित किए गए अच्छी तरह से तय किए गए सिद्धांतों को उद्धृत आदेशना चाहते हैं, जिन्हें परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराते समय निचली अदालतों द्वारा निकाले गए निष्आदेशों की जांच आदेशने के लिए लागू किया जाना है। उन निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों का उल्लेख यह पता लगाने से पहले किया जा सकता है कि क्या अपीलकर्ता पर दोषसिद्धि और सजा को स्थापित किया जा सकता है या नहीं, जैसा कि उच्च निचली अदालत के साथ-साथ विद्वत विचारण निचली अदालत के फैसले में कहा गया है। इन सिद्धांतों को निम्नानुसार निर्धारित किया जा सकता हैः

10.1.जिन परिस्थितियों से अपराध के निष्कर्ष को साबित करने की कोशिश की जाती है, उन्हें दृढ़ता से या दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए।

10.2.परिस्थितियां निश्चित रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करने वाली होनी चाहिए।

10.3.संचयी रूप से ली गई परिस्थितियों को एक ऐसी श्रृंखला बनानी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि इस निष्कर्ष से कोई बच न सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर, अपराध आरोपी द्वारा किया गया था और कोई और नहीं।

10.4.दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या आदेशने में पूर्ण और असमर्थ होना चाहिए और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होना चाहिए बल्कि उसकी निर्दोषता के साथ असंगत होना चाहिए'"

(जोर दिया गया)

9. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामले से संबंधित उपरोक्त कानूनी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, जब हम संबंधित वकील की दलीलों पर विचार करते हैं, तो श्री सुशील कुमार, अपीलकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील, मामले की उत्पत्ति और विभिन्न तिथियों का उल्लेख करने के बाद, जिन पर पुलिस द्वारा विभिन्न अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया था, मामले को नियमित पुलिस से सीबीआई को स्थानांतरित करने और आरोपी के खिलाफ दायर आरोप-पत्र में बताया गया है कि अपीलकर्ता के खिलाफ ए-5 से ए-14 के साथ आरोप भा.दं.सं. की खंड 120बी के साथ-

साथ खंड 302 के तहत थे, जबकि ए-2 को छोड़कर ए-1 से ए-4 तक, भा.दं.सं. की खंड 34 के साथ पठित खंड 120बी और 302 के तहत आरोप लगाए गए थे। ए-2 पर आई. पी. सी. की खंड 120बी के साथ खंड 305 के तहत आरोप लगाया गया था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि ए-1 से ए-4 पर आई. पी. सी. की खंड 34 के साथ पठित खंड 302 के तहत आरोप लगाया गया है और चश्मदीद गवाह के खाते के आधार पर उक्त अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, ए-5 से ए-14 के खिलाफ अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से आई. पी. सी. की खंड 120 बी के तहत मृतक की कथित हत्या के लिए आई. पी. सी. की खंड 302 के तहत दोषी ठहराए जाने के आरोप पर आधारित है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे बताया कि अपीलकर्ता को ए-11 के साथ और उच्च परिप्रेक्ष्य में ए-14 के साथ जोड़ा गया था और प्रस्तुत किया कि ए-14 को निचली अदालत ने बरी कर दिया था और ए-11 को वरिष्ठ अधिवक्ता ने बरी कर दिया था। ए-11 और ए-14 के साथ ए-10 की संलिप्तता के संबंध में निचली अदालत और वरिष्ठ अधिवक्ता के उक्त निष्कर्षों का उल्लेख करते हुए, जिसके परिणामस्वरूप ए-11 और ए-14 को दोषमुक्ति दिया गया, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि ए-10 को उक्त समूह से बाहर करके उसे दोषी ठहराना किसी भी कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य या कानून के सिद्धांतों द्वारा समर्थित नहीं था।

10. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह कहते हुए अपनी प्रस्तुति की शुरुआत की कि ए-1 द्वारा ए-4 को 22.07.1994 पर आत्मसमर्पण करने के तुरंत बाद, राज्य पुलिस के समक्ष किसी भी स्वीकारोक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता था क्योंकि यह साक्ष्य अधिनियम, 1872 की खंड 25 द्वारा प्रभावित था। हम उक्त समर्पण में बल पाते हैं। इसलिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यदि ए-10 की दोषसिद्धि को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर बरकरार रखा जाना है, तो मूल सिद्धांतों, अर्थात्, अपीलकर्ता के खिलाफ परिस्थितियों की श्रृंखला का निर्णायक प्रमाण स्थापित किया

जाना चाहिए था और उक्त सिद्ध परिस्थितियों से अपीलकर्ता के अपराध की एकमात्र परिकल्पना की जानी चाहिए थी, न कि इसके विपरीत।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने विद्वत विचारण न्यायाधीश के साथ-साथ वरिष्ठ अधिवक्ता के निष्कर्षों का उल्लेख करते हुए, जिसके द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ ऐसी महत्वपूर्ण परिस्थितियों को किसी भी कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किया गया था, तर्क दिया कि निचली अदालत द्वारा अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा इसकी पुष्टि गलत थी और कानूनी सिद्धांतों के खिलाफ थी और परिणामस्वरूप अपील की अनुमति दी जानी चाहिए।इसलिए, उन्होंने तर्क दिया कि जब अभियुक्तों के खिलाफ भा.दं.सं. सी. की खंड 120 बी के तहत कार्रवाई की गई थी और अपीलकर्ता के साथ जिन अभियुक्तों को फंसाया गया था, उन सभी को भा.दं.सं. सी. की खंड 120 बी के तहत आरोप से बरी कर दिया गया था, तो अकेले अपीलकर्ता को दोषी ठहराने की कोई गुंजाइश नहीं थी।

11. उपरोक्त प्रस्तुतियों के विरुद्ध, सी. बी. आई. की विद्वत स्थायी वकील सुश्री मधुरिमा तातिया ने तर्क दिया कि ए-11 और ए-14 की तुलना में अपीलकर्ता के मामले में विशिष्ट विशेषताएं थीं और इसलिए, निचली अदालत द्वारा भा.दं.सं. सी. की खंड 120 बी और उच्च न्यायालय द्वारा ए-11 के तहत आरोप से ए-14 का बहिष्करण और उनके परिणामी दोषमुक्ति का अपीलकर्ता की दोषसिद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है।उस संदर्भ में विद्वान अधिवक्ता ने भौतिक साक्ष्य के आधार पर विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय के निष्कर्षों का उल्लेख किया, अर्थात्, मृतक और ए-14 के साथ अपीलकर्ता के पहले के मैत्रीपूर्ण संबंध, ए-14 की स्थिति में बाद में सुधार जिसने उसे बड़ी मात्रा में धन प्राप्त करने में सक्षम बनाया, मृतक द्वारा विकसित आकर्षक व्यवसाय जो उसके लिए आजीविका का नियमित स्रोत प्रदान करता था, जबकि अपीलकर्ता की स्थिति अनिश्चित बनी रही, जिसने समय के साथ नाराज़गी और मृतक को खत्म करने का उद्देश्य पैदा किया।विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि भारी सबूत, अर्थात्, अपीलकर्ता

के खिलाफ मृतक द्वारा दायर किया गया मुकदमा, साथ ही साथ, अंबाला में उसके द्वारा संचालित पेट्रोल पंप के संबंध में कुछ अन्य पक्षकार, अपीलकर्ता द्वारा स्वयं मृतक के खिलाफ मुकदमा दायर किया जा रहा है ताकि उसे उक्त व्यवसाय चलाने से रोका जा सके और पेट्रोलियम व्यवसाय में हिस्सा पाने के उसके प्रयास में विफलता, वे सभी परिस्थितियाँ थीं जो व्यक्तिगत रूप से अपीलकर्ता के खिलाफ साबित हुईं और मृतक की हत्या के लिए एक ठोस उद्देश्य का निर्माण किया।विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया कि उपरोक्त साक्ष्य के अलावा, ए-1 उसका भतीजा था जो मुख्य रूप से अपीलकर्ता की व्यावसायिक गतिविधियों में भी भाग ले रहा था और इसलिए, ए-2 से ए-4 की मदद से मृतक की हत्या के लिए अपीलकर्ता द्वारा ए-1 की नियुक्ति संतोषजनक रूप से स्थापित की गई थी।इसलिए, सी. बी. आई. के विद्वान स्थायी वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के फैसले में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

12. अपीलकर्ता के साथ-साथ प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और निचली अदालत और उच्च न्यायालय के फैसले का अध्ययन करने के बाद, सी. बी. आई. की ओर से की गई प्रस्तुति का उल्लेख करते हुए हमने नोट किया है कि उक्त प्रस्तुति ने 14 अभियुक्तों को उनके खिलाफ लगाए गए षड्यंत्र के उद्देश्य से तीन समूहों में वर्गीकृत किया है।पहले समूह में ए-14 और ए-10 को एक साथ जोड़ा गया था। वास्तव में सी. बी. आई. के अनुसार, दो प्रमुख साजिशकर्ताओं, ए-14 और ए-10 में से ए-14 मुख्य साजिशकर्ता माना जाता था, जबकि अपीलकर्ता (ए-10) जल्लाद था।इस मोड़ पर, यह कहना प्रासंगिक है कि हालांकि ए-14 को निचली अदालत द्वारा बरी कर दिया गया था, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, उच्च न्यायालय ने ए-14 को दोषमुक्ति के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और राज्य ने इसे इस अदालत में चुनौती देने का विकल्प नहीं चुना है।इसलिए ए-14 को दोषमुक्तिना अंतिम और निर्णायक हो गया है।

13. जहां तक साजिशकर्ताओं के दूसरे समूह का संबंध है, सीबीआई के अनुसार, यह ए-5, ए-6, ए-7, ए-8, ए-9, ए-11 ए-12 और ए-13 से संबंधित है, जिनमें से ए-11 को छोड़कर सभी को निचली अदालत ने साजिश के आरोप से बरी कर दिया था। हालांकि, ए-11 को उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया था।यहां फिर से, राज्य ने ए-11 के दोषमुक्ति के खिलाफ कोई अपील दायर करने का विकल्प नहीं चुना है, जो इसलिए अंतिम और निर्णायक हो गया है।

14. साजिशकर्ताओं के तीसरे समूह, ए-1 से ए-4 को अनुबंध हत्यारे कहा गया था। सी. बी. आई. के अनुसार, मृतक की हत्या में तीनों समूहों में से प्रत्येक का मकसद अलग-अलग था। पहले समूह के संबंध में, यह तर्क दिया गया था कि इसका उद्देश्य पेट्रोल पंप का अधिग्रहण करना था और उस उद्देश्य के लिए जो भी उनके रास्ते में आया उसे समाप्त कर देना था।इसके परिणामस्वरूप मृतक की हत्या कर दी गई। जहाँ तक दूसरे समूह का संबंध था, यह केवल इतना कहा गया था कि उक्त समूह ने साजिशकर्ताओं के पहले समूह की मदद की, क्योंकि वे उनके करीबी दोस्त थे।अंत में, जहां तक साजिशकर्ताओं के तीसरे समूह का सवाल है, यह तर्क दिया गया कि पेशेवर होने के नाते, उनका एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना था और कुछ नहीं।

15. अभियुक्त के खिलाफ साजिश की उपरोक्त तीन-आयामी कहानी के साथ, निचली अदालत को ए-5 से ए-9 और ए-12 से ए-14 के खिलाफ साजिश का समर्थन करने के लिए कोई स्वीकार्य सामग्री सबूत नहीं मिला।इस प्रकार, दूसरे समूह में साजिशकर्ताओं के एक बड़े समूह के साथ-साथ तथाकथित प्रमुख साजिशकर्ता को भी उनके खिलाफ कथित साजिश का हिस्सा नहीं पाया गया। यद्यपि राज्य ने पहले समूह के तहत आने वाले तथाकथित प्रमुख साजिशकर्ता के दोषमुक्ति को चुनौती देना उचित समझा, लेकिन राज्य ने दूसरे समूह के तहत आने वाले साजिशकर्ताओं के दूसरे समूह के दोषमुक्ति को स्वीकार कर लिया। उस प्रक्रिया में जो बचा था वह अपीलकर्ता (ए-10),

ए-11 और ए-14 के खिलाफ कथित साजिश थी।जहाँ तक ए-1 से ए-4 यानी तीसरे समूह का संबंध है, यह बहुत हद तक सच है कि उन्होंने चश्मदीद गवाहों की उपस्थिति में एक समान इरादे से मृतक की संयुक्त रूप से हत्या की थी, जिस पर निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने भी सही भरोसा किया था।इसलिए, हत्या में सीधे भाग लेने वाले अभियुक्तों के उक्त समूह की दोषसिद्धि की पुष्टि करने में कोई कठिनाई नहीं है और जिन्हें भा.दं.सं. सी. की खंड 34 के साथ पठित खंड 242 के तहत सही तरीके से दोषी ठहराया गया था।

16. उपर्युक्त प्रस्तावना के साथ, जब हम अपीलकर्ता के मामले की जांच करते हैं, तो हमें आवश्यक रूप से सभी प्रासंगिक परिस्थितियों के साथ अपीलकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के प्रस्तुत करने पर विचार करना होगा, जिन पर अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किया गया था और मुख्य रूप से ए-11 और ए-14 के साथ अपीलकर्ता के खिलाफ केंद्रित था, विशेष रूप से ए-14 के साथ।वास्तव में, विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता और ए-11 के साथ ए-14 को जोड़ने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई निर्णायक संबंध नहीं पाया और व्यापक रूप से कहा कि ए-10 और ए-11 का मृतक की हत्या के बाद भागने में आचरण जब तक कि वे अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों के साथ विचार करने पर ए-10 और ए-11 के साथ ए-1 से 4 के अपराध को साबित करते हैं। मृतक की हत्या के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में ए-11 के साथ अपीलकर्ता के उक्त आचरण का उल्लेख करते हुए और उस प्रयास में मृतक द्वारा पेट्रोलियम व्यवसाय की स्थापना से पहले ए-14 के साथ अपीलकर्ता के पहले के घनिष्ठ संबंध, काला अम्ब में पहले की गई साजिश जो अमल में नहीं आई, 16.07.1994 और 27.07.1994 के बीच ए-14 के कर्मचारी के साथ अपीलकर्ता का टेलीफोन संपर्क, ए-1 के साथ अपीलकर्ता के संबंध सभी पर विचार किया गया। लेकिन यहां तक कि उपरोक्त कई परिस्थितियों के संदर्भ में निचली अदालत के निष्कर्ष भी बिना किसी विराम के

परिस्थितियों की एक श्रृंखला को दिखाने के लिए इतने मूर्खतापूर्ण नहीं थे और इसलिए, हम महसूस करते हैं कि कहीं अधिक गंभीर विचार किए जाने की आवश्यकता है।इसके अलावा, जब हमने उच्च न्यायालय के विवादित फैसले का अध्ययन किया, तो हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष के मामले को प्रतिग्रहण करना आदेशने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला के संदर्भ में बिगड़ते कारकों को उजागर आदेशने वाले कुछ निश्चित निष्आदेश थे।

17. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने बाद में निचली अदालत के समक्ष रखी गई विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर निचली अदालत के समक्ष सी. बी. आई. की समापन दलीलों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया ताकि यह तर्क दिया जा सके कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, ए-14 मृतक द्वारा विकसित व्यवसाय में एक हिस्सा प्राप्त करके अंतिम लाभार्थी होने की मांग कर रहा था, जिससे उसे खत्म करने का सबसे मजबूत उद्देश्य बना और यह कि अपीलकर्ता के पूर्ण समर्थन के साथ इसे अच्छी तरह से योजनाबद्ध और निष्पादित किया गया था जो पूरी तरह से उसके साथ जुड़ा हुआ था। इस तरह के जुड़ाव को शुरू से ही कहा जाता था, यानी ए-14 के राजनीति में पैर जमाने से पहले और बाद में जब वह स्वास्थ्य और समाज कल्याण को संभालने वाले मंत्री का दर्जा रखते थे।निचली अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से की गई कथित प्रस्तुति का उल्लेख करते हुए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि महत्वपूर्ण परिस्थितियों में से एक, अर्थात्, अपीलकर्ता द्वारा घटना के अगले दिन पी. डब्ल्यू.-28 को किया गया कथित टेलीफोन कॉल, जो चंडीगढ़ में ए-14 का कर्मचारी था, जिससे अपीलकर्ता ने ए-14 के आवास से मसूरी में ए-1 के ठिकाने के बारे में पूछताछ की थी, जिसे स्थापित नहीं किया गया था।

18. निचली अदालत ने इस प्रभाव के लिए एक स्पष्ट निष्कर्ष दिया है कि मोहन लाल (पीडब्लू-39) के साथ-साथ अनूप गुप्ता (पीडब्लू-46) के साक्ष्य अभियोजन पक्ष के

उक्त संस्करण का समर्थन नहीं करते हैं और यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता अंबाला से अपनी कार में ए-11 के साथ करनाल के लिए गया था या रास्ते में उसने अंबाला और चंडीगढ़ में ए-14 के आवास पर कोई टेलीफोन कॉल किया था।हम अभियोजन पक्ष द्वारा उसके समक्ष रखे गए साक्ष्य के आधार पर निचली अदालत द्वारा दिए गए उक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए अभियोजन पक्ष के मामले में पर्याप्त कमी पाते हैं।

19. श्री सतपाल सहगल (पीडब्लू-42) द्वारा ए-10 और ए-11 की गिरफ्तारी से संबंधित एक अन्य परिस्थिति जिसे निचली अदालत के समक्ष रखा गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीडब्लू-42 उस कार का चालक था जिसमें अपीलकर्ता, ए-11 और अन्य आरोपी, ए-6 और ए-7 ने अंबाला से करनाल के लिए आईडी-2 पर यात्रा की और उन्होंने आईडी-1 पर शाम करीब 7-8 बजे पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।वास्तव में, अरुण कुमार हांडा (पीडब्लू-28), पीडब्लू-39 और पीडब्लू-46 के साक्ष्यों पर भरोसा करके, निचली अदालत एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंची कि यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि अपीलकर्ता अंबाला से ए-6, ए-7 और ए-11 के साथ करनाल के लिए अपनी कार में 16.07.1994 पर गया था या उसने अंबाला और चंडीगढ़ में ए-14 के निवासियों को कोई टेलीफोन कॉल किया था। इस सवाल पर विचार करते हुए कि ए-10 और ए-11 को किस तारीख को हिरासत पूर्वाहन लिया गया था, निचली अदालत ने पीडब्लू-42 के संस्करण का हवाला देते हुए कहा कि पीडब्लू-53 के संस्करण के अनुसार, इंस्पेक्टर रिशाल सिंह, अपीलकर्ता को पुलिस स्टेशन सदर, अंबाला पूर्वाहन 27.07.1994 पर सुबह 11.30 पर ले जाया गया था और जैसा कि पीडब्लू-42 द्वारा 26.07.1997 पर कथित आत्मसमर्पण के संबंध पूर्वाहन कहा गया संस्करण ही सच नहीं था।इसलिए, यदि पीडब्लू-53 के संस्करण के अनुसार इंस्पेक्टर रिशाल सिंह, अपीलकर्ता और ए-11 को 27.07.1994 पर गिरफ्तार किया गया था, तो पीडब्लू-42 के

संस्करण पर भरोसा करना पूरी तरह से असुरक्षित होगा जैसा कि अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा सही तर्क दिया गया है।

20. जहां तक इस आरोप का संबंध है कि ए-14 इस आधार पर मुख्य साजिशकर्ता था कि मृतक की हत्या का सीधा मकसद था क्योंकि मृतक ने अपने अवैध दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया था, निचली अदालत ने विस्तृत तर्क देते हुए ए-14 के खिलाफ उक्त परिस्थिति को खारिज कर दिया।निचली अदालत ने कहा कि मृतक की हत्या आदेशने के लिए एक साथ साजिश रचने के लिए अन्य अभियुक्तों के साथ ए-14 को शामिल आदेशने का कोई सबूत नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा कहे गए किसी भी कार्य या शब्दों का कोई सबूत नहीं है जिससे किसी भी साजिश में उनके निहितार्थ का अनुमान लगाया जा सके। निचली अदालत ने काला अम्ब में आयोजित किए गए पहले के षड्यंत्र पर विचार करते हुए भी कहा कि यह साबित नहीं हुआ था और अन्य लोगों के साथ ए-14 की साजिश को साबित करने के लिए किसी भी गवाह द्वारा से कोई स्वीकार्य सबूत नहीं था। इसलिए, ट्रायल कोर्ट ने पाया कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य से केवल यह पता चलता है कि मृतक, ए-14 और ए-10 सभी दोस्ताना संबंधों में थे और कुछ और नहीं।

21. विचारण न्यायालय के उपरोक्त निर्दिष्ट निश्चित निष्कर्षों पर ध्यान देने के बाद, हम यह भी पाते हैं कि विचारण न्यायालय ने यह विचार रखा कि ए-5 से ए-9 और ए-12 से ए-14 के विरुद्ध षड्यंत्र का सिद्धांत स्थापित नहीं किया गया था और ए-10 और ए-11 का मामला एक अलग आधार पर खड़ा था। उक्त दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए विचारण न्यायालय के साथ जिन कारणों पर विचार किया गया, वे परिस्थितियों पर आधारित थे, अर्थात्, ए-10 और ए-11 एक साथ चल रहे थे और 16.07.1994 से तुरंत भाग रहे थे, उनके समर्पण के अनुसरण में 27.07.1994 पर उनकी गिरफ्तारी, उनकी गिरफ्तारी से बचने के लिए ए-10 और ए-11 का एक स्थान से

दूसरे स्थान पर भागना, ए-10 ने मृतक के खिलाफ पेट्रोल पंप के संचालन पर रोक लगाने के लिए मुकदमा दायर किया, ए-10 को उस संबंध में मृतक के खिलाफ शिकायत थी, कि पहला आरोपी जो मृतक की हत्या के वास्तविक कार्य में सक्रिय भाग ले रहा था, वह अपीलकर्ता का भतीजा था, कि उसके घनिष्ठ संबंध के कारण वह अपीलकर्ता के बाजार की देखभाल कर रहा था और ए-10 और ए-11 दोनों।इसलिए, अपीलकर्ता और ए-11 के उपरोक्त कृत्यों ने मृतक के उन्मूलन में आरोपी ए-1 से ए-4 के साथ उनकी साजिश की ओर इशारा किया।

22. अभियुक्त के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा किए गए विभिन्न निष्कर्षों और निष्कर्षों को नोट करने के बाद, हम पाते हैं कि अभियुक्त के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा निम्नलिखित प्रासंगिक परिस्थितियों पर भरोसा किया गया था।परिस्थितियाँ इस प्रकार थींः-

(ए) ए-14, ए-10 और मृतक एक समय में बहुत अच्छे दोस्त थे।

(बी) समय के साथ, ए-14 ने राजनीति में अपने पैर जमा लिए और अंततः एक ऐसे स्तर पर पहुंच गए जब वे राज्य सरकार में स्वास्थ्य के साथ-साथ राजस्व विभाग के मंत्री बने।

(सी) मृतक अपने स्वयं के प्रयासों से अंबाला में एक पेट्रोल पंप स्थापित करने में समर्थ था।

(डी) ए-14 के साथ ए-10 मृतक द्वारा विकसित पेट्रोलियम व्यवसाय में हिस्सा लेना चाहता था, जो मृतक को स्वीकार्य नहीं था।

(ई) चूंकि मृतक ए-10 के साथ ए-14 के दबाव के आगे नहीं झुके, इसलिए मृतक को खत्म करने के लिए 'काला अम्ब' नामक स्थान पर पहले साजिश रची गई थी, जो सफल नहीं हुई।

(एफ) ए-10 ने मृतक को पेट्रोल पंप चलाने से रोकने के लिए उसके खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया।

(जी) ए-10 ने मृतक की हत्या के लिए ए-2 से ए-4 के साथ ए-1 की स्थापना की क्योंकि ए-1 उसका भतीजा था और अपीलकर्ता की सभी व्यावसायिक गतिविधियों की देखभाल भी कर रहा था।

(एच) साजिश के हिस्से के रूप में, ए-10 ने पीडब्लू-36 से कार और ए-9 से बंदूक खरीदी और दोनों को मृतक को मारने की योजना को लागू करने के लिए ए-1 को सौंप दिया।

(आई) 16.07.1994 पर मृतक की हत्या के बाद और बाद में A-1 से A-4 ने 22.07.1994 पर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, A-10 A-11 के साथ एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा था ताकि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने से बचा जा सके।

(जे) पीडब्लू-42 वह चालक था जो उस वाहन को चला रहा था जिसमें ए-10 और अन्य 16.07.1994 के बाद यात्रा कर रहे थे, जब तक कि उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया।

(के) जब वह भाग रहा था, अपीलकर्ता ने ए-14 के आधिकारिक आवास पर टेलीफोन किया, अपने कर्मचारी पीडब्लू-36 से यह पता लगाने के लिए बात की कि मसूरी में ए-1 से ए-4 कहाँ रह रहे थे।

(एल) कोई रास्ता न पाते हुए, अंततः ए-11 के साथ अपीलकर्ता (ए-10) ने पी. डब्ल्यू.-53 रिशाल सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जो जांच से जुड़े थे, हालांकि पी. डब्ल्यू.-42, चालक के अनुसार, आत्मसमर्पण लगभग 7/8 बजे हुआ।

23. जब उपरोक्त परिस्थितियों पर भरोसा किया गया, तो निचली अदालत ने जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, पाया है कि ए-14 की साजिश में कोई भूमिका नहीं थी और मृतक की हत्या में ए-14 को शामिल करने के लिए कोई निर्णायक परिस्थिति नहीं थी। निचली अदालत ने यह भी पाया कि अन्य आरोपी ए-5 से ए-9 और ए-12 और ए-13 ने भी कथित साजिश में कोई भूमिका नहीं निभाई और उन्हें बरी कर दिया गया।अंततः, ए-1 से ए-4 को पीडब्लू-22,23 और 25 द्वारा से प्रत्यक्ष साक्ष्य के आधार पर मृतक की हत्या का दोषी पाया गया, अर्थात् मृतक का भाई, ढिल्लों ईंधन स्टेशन का मालिक और सेल्समैन सुरजीत सिंह जहाँ तक ए-10 और ए-11, अर्थात् अपीलकर्ता और कमलजीत सिंह उर्फ लाली का संबंध है, हालाँकि निचली अदालत ने दोनों को साजिश के साथ-साथ मृतक की परिणामी हत्या का दोषी पाते हुए एक ही आधार पर रखा, उच्च न्यायालय ने ए-11 को क्लीन चिट दे दी।निचली अदालत ने अपीलकर्ता (ए-10) और ए-11 को इस एकल तथ्य के आधार पर एक समान स्थिति में रखा कि वे दोनों पुलिस के चंगुल से बचने के लिए ए-1 से ए-4 के आत्मसमर्पण के बाद आदेश रहे थे।हालाँकि, उच्च न्यायालय ने सही पाया है कि ए-11 के खिलाफ भा.दं.सं. सी. की खंड 120 बी के तहत साजिश के आरोप के लिए आत्यन्तिक रूप कुछ भी नहीं था, जिसके बिना उसे भा.दं.सं. सी. की खंड 302 के तहत हत्या के आरोप में शामिल करने का कोई सवाल ही नहीं था।

24. उपरोक्त अंतिम निष्कर्षों के आलोक में, जब हम उच्च न्यायालय के विवादित फैसले का विश्लेषण करते हैं कि ए-1 से ए-4 तक की साजिश और मृतक की अंतिम हत्या में अपीलकर्ता की हर भूमिका थी, तो हम पाते हैं कि उक्त निष्कर्ष उन कारकों पर आधारित था जो खण्ड पीठ के फैसले के निम्नलिखित पैराग्राफ में संक्षेप में बताए गए हैंः

"क्या यह कहा जा सकता है कि निर्मल सिंह के बारे में जो सच है वह बलकार सिंह चुडियाला के बारे में भी सच था।यह आरोपी वह व्यक्ति था जिसने हमलावरों को बंदूक और कार प्रदान की थी।वह आत्मसमर्पण करने से पहले 10 दिनों तक छिपने के लिए घटना के बाद भाग गया था।यह कहा जा सकता है कि बलकार सिंह चुडियाला भी फरार था क्योंकि वह जानता था कि उसे अपने दोस्त की हत्या के साजिशकर्ता के रूप में नामित किया जाएगा।निर्मल सिंह की तुलना में बलकार सिंह चुडियाला पर अधिक दांव था। उत्तरार्द्ध एक मंत्री था और राजनीतिक शक्ति और संरक्षण का आनंद लेता था, जबकि पूर्व केवल एक हैंगर-ऑन था, एक ऐसा व्यक्ति जो सतिंदर सेखों या अपने पेट्रोल पंप से कोई लाभ प्राप्त करने में असमर्थ था।निर्मल सिंह को राजनीतिक सत्ता मिली थी, सतिंदर सेखों को पेट्रोल पंप मिला था जो वह चाहते थे लेकिन बलकार सिंह चुडियाला को कुछ नहीं मिला। इसलिए, बलकार सिंह चुडियाला का सतिंदर सेखों की हत्या कराने का मकसद मजबूत था।वास्तव में, न तो बलकार सिंह चुडियाला और न ही निर्मल सिंह ने कभी कोई अच्छा काम किया था, लेकिन कम से कम निर्मल सिंह ने सरकार में एक ऐसे पद से बरी कर दिया था जिससे उन्हें धन अर्जित करने का पर्याप्त अवसर मिला था।बलकार सिंह चुडियाला एक असफल और ड्रॉप-आउट थे।बलकार सिंह चुडियाला का सतिंदर सेखों की हत्या की साजिश रचने का मकसद मजबूत और आश्वस्त करने वाला था।

कमलजीत सिंह उर्फ लाली के मामले में, यह आरोपी घटना के बाद केवल बलकार सिंह चुडियाला के साथ चला गया था, लेकिन सतिंदर

सेखों के खिलाफ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी या द्वेष नहीं था।कमलजीत सिंह के मामले में जिस सवाल पर विचार किया जाना है, वह यह है कि क्या मुख्य आरोपी के साथ उसका जाना इस तरह के आचरण के बराबर होगा जो उसे एक साजिशकर्ता के रूप में फंसाता है।हमें नहीं लगता कि इस तरह का निष्कर्ष निकाला जा सकता है।" (रेखांकित करना हमारा है)

25. जब हम खण्ड पीठ के उपरोक्त पैराग्राफ और उन कारकों का उल्लेख करते हैं जो एक साजिश के आधार पर ए-1 से ए-4 के साथ मृतक की हत्या के लिए अपीलकर्ता को अलग करने में निचली अदालत के साथ वजन करते हैं, तो हम पाते हैं कि निचली अदालत ने ए-1 के साथ अपीलकर्ता के संबंध और मृतक की हत्या के बाद उसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागने को अधिक प्रासंगिक कारक के रूप में ध्यान में रखा।खण्ड पीठ ने अपीलकर्ता द्वारा हमलावरों को बंदूक और कार प्रदान करने के तथ्य के अलावा घटना के बाद छिपकर भागने के प्रयास और इस तथ्य पर भरोसा किया कि तीन दोस्तों, ए-14, ए-10 और मृतक के बीच, अकेले अपीलकर्ता को आर्थिक या किसी भी स्थिति से बहुत अधिक लाभ नहीं हुआ और यह मृतक को खत्म करने के लिए अपीलकर्ता के लिए एक बड़ा उद्देश्य था।

26. इसलिए, विचार करने के लिए प्रश्न यह है कि क्या उन कारकों को पर्याप्त परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए माना जा सकता है या इसे अधिक सटीक रूप से स्थापित करने वाली परिस्थितियों के रूप में रखा जा सकता है जो साजिश और मृतक की परिणामी हत्या के लिए अपीलकर्ता के अपराध को साबित करने के लिए कानून को ज्ञात तरीके से स्थापित हैं। आपराधिक मामले में विश्वास किए जाने पर षड्यंत्र के सिद्धांतों और परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में निचली अदालत द्वारा की गई

वैचारिक टिप्पणी को दोहराना सार्थक होगा।विचारण न्यायालय द्वारा उल्लिखित वे अवधारणाएँ इस प्रकार थींः

> "351. यह तय किया गया कानून है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सराहना करते हुए, अदालत को एक बहुत ही सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और केवल तभी दोषसिद्धि दर्ज करनी चाहिए जब श्रृंखला में सभी लिंक अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करते हुए पूर्ण हों और निर्दोषता की प्रत्येक परिकल्पना सबूत पर नकारने में सक्षम हो।परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मूल्यांकन करने में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है और यदि जिस साक्ष्य पर भरोसा किया गया है वह दो निष्कर्षों के लिए यथोचित रूप से सक्षम है, तो अभियुक्त के पक्ष में एक को स्वीकार किया जाना चाहिए।जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित पाया जाना चाहिए और इस तरह से स्थापित सभी तथ्यों का संचयी प्रभाव केवल अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए। षड्यंत्र के आरोप को साबित आदेशने के लिए यह आवश्यक है कि अभियोजन पक्ष को उस स्थान या स्थानों के नाम, इसे बनाने वाले व्यक्तियों के नाम और इसे कैसे बनाया गया था, यह साबित आदेशना चाहिए।"
>
> (रेखांकित करना हमारा है)

27. विचारण न्यायालय द्वारा यह उचित रूप से नोट किया गया है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सराहना करते हुए, न्यायालय को एक बहुत ही सतर्क दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और केवल तभी दोषसिद्धि दर्ज करनी चाहिए जब

परिस्थितियों की श्रृंखला में सभी संबंध अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करते हुए पूर्ण हों और निर्दोषता की प्रत्येक परिकल्पना साक्ष्य पर नकारने में सक्षम हो। इसने यह भी कहा कि परिस्थितियों का मूल्यांकन करने में बहुत सावधानी बरतनी होगी और यदि साक्ष्य दो निष्कर्षों के लिए यथोचित रूप से सक्षम है, तो अभियुक्त के पक्ष में एक को स्वीकार किया जाना चाहिए और जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया गया है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित पाया जाना चाहिए और इस तरह से स्थापित सभी तथ्यों का संचयी प्रभाव केवल अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए। इसी तरह, जहां तक साजिश का संबंध है, निचली अदालत ने ठीक ही कहा है कि साजिश के आरोप को साबित आदेशने के लिए, यह आवश्यक है कि अभियोजन पक्ष को उस स्थान या स्थानों के नाम, इसे बनाने वाले व्यक्तियों के नाम और इसे कैसे बनाया गया था, यह साबित आदेशना चाहिए। हम पाते हैं कि किसी मामले की उपरोक्त समझ की सराहना की जानी चाहिए जब यह साजिश के आरोप के साथ परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित थी, जिसे निचली अदालत ने पूरी तरह से नोट किया था।

28. तथापि, हम पाते हैं कि उसके द्वारा उल्लिखित सिद्धांतों को लागू करते समय, विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने सिद्धांतों को पूरी तरह से मंजूरी दे दी है और वास्तव में खण्ड पीठ ने एक स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाया और उन परिस्थितियों से संबंधित अपने स्वयं के निष्कर्षों के साथ एक विरोधाभासी निष्कर्ष दिया जो अपीलकर्ता से संबंधित थे। उच्च न्यायालय ने उन तीन परिस्थितियों का सही उल्लेख किया जो अपीलकर्ता को साजिश और मृतक की परिणामी हत्या में शामिल आदेशने के लिए वास्तव में प्रासंगिक थीं।वे परिस्थितियाँ अपीलकर्ता का आचरण था कि उसने पीडब्लू-36 से कार और ए-9 से बंदूक खरीदी और दोनों को अपने भतीजे ए-1 को सौंप दिया।जहाँ तक उक्त परिस्थिति का संबंध है, खण्ड पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दिया हैः

"छठी स्थिति यह थी कि बलकार सिंह चुडियाला ने स्वर्ण सिंह से कार और दलबीर सिंह से बंदूक खरीदी और दोनों को बलदेव सिंह को सौंप दिया।दोनों परिस्थितियों को बिना सबूत के पाया गया क्योंकि स्वर्ण सिंह ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया था।बलदेव सिंह से दलबीर सिंह की बंदूक की बरामदगी, हालांकि यह साबित नहीं हुई कि बलदेव सिंह को बंदूक बलकार सिंह चुडियाला ने दी थी।बलदेव सिंह के इस खुलासा बयान का हिस्सा कि उन्हें बलकार सिंह चुडियाला से बंदूक मिली थी, इस तरह से साबित नहीं किया जा सका"

29. दूसरी परिस्थिति ए-11 के साथ अपीलकर्ता का अलग-अलग स्थानों पर भागना था।उक्त परिस्थिति के संदर्भ में भी खण्ड पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि उक्त परिस्थिति को साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है, जिसका निष्कर्ष निम्नलिखित पैराग्राफ में दिया गया हैः

"उन्नीसवीं परिस्थिति में, बलकार सिंह चुडियाला और कमलजीत सिंह गिरफ्तारी से बचने के लिए दोराहा, लुधियाना, कोट कापुरा और फिर चंडीगढ़ भाग गए। वे निर्मल सिंह के 118, सेक्टर 8, चंडीगढ़ स्थित आधिकारिक आवास पर भी रुके थे।विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि निर्मल सिंह द्वारा बलकार सिंह चुडियाला को शरण देने का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है।"

30. एक अन्य स्थिति जिस पर ध्यान दिया गया वह बीसवीं स्थिति थी जो फिर से ए-9 की बंदूक से संबंधित थी जिसे अपीलकर्ता के भतीजे ए-1 के कहने पर बरामद किया गया था।उक्त परिस्थिति के संबंध में, खण्ड पीठ का निष्कर्ष इस प्रकार थाः

"अभियोजन पक्ष जिस बीसवीं परिस्थिति पर निर्भर था, वह थी दलबीर सिंह द्वारा हत्या के लिए बलकार सिंह चुडियाला को प्रदान की गई बंदूक और उसी बंदूक का इस्तेमाल बलदेव सिंह द्वारा गवाहों को आतंकित करने के लिए किया गया था।बंदूक को गुरदेव सिंह ने अपने ट्यूबवेल पर छुपाया था और अपने खुलासा बयान के आधार पर 22 जुलाई को वहां से बरामद किया था।विद्वान न्यायाधीश ने बलकार सिंह चुडियाला द्वारा दलबीर सिंह से बंदूक की खरीद पर विश्वास नहीं किया, बलकार सिंह चुडियाला ने इसे बलदेव सिंह को सौंप दिया, क्योंकि हालांकि यह बलदेव सिंह के प्रकटीकरण बयान का एक हिस्सा था, लेकिन इससे किसी भी तथ्य की खोज नहीं हुई थी।"

31. एक अन्य परिस्थिति, जिसे अंतिम परिस्थिति के रूप में नोट किया गया था, वह थी जगमोहन सिंह भल्ला (पीडब्लू-17) और ए-13 के बीच तथाकथित टेलीफोन वार्तालाप, यानी मृतक की हत्या के बाद, जिसके संदर्भ में खण्ड पीठ ने यह भी माना कि यह ए-13 से संबंधित होने तक पूरी तरह से अपर्याप्त था।उक्त परिस्थिति पर खण्ड पीठ द्वारा निम्नलिखित पैराग्राफ में विचार किया गया हैः

"सभी 14 अभियुक्तों के बीच साजिश के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा जिस अंतिम परिस्थिति पर भरोसा किया गया था, वह यह थी कि दर्शन सिंह ने 17 जुलाई को जगमोहन भल्ला (पीडब्लू 17) को फोन करके सूचित किया था कि सतिंदर सेखों की हत्या कर दी गई है। जगमोहन भल्ला ने जवाब दिया कि उन्हें केवल पिटाई करने के लिए सतिंदर सेखों को काला अम्ब तक लुभाने के लिए कहा गया था, लेकिन दर्शन सिंह ने उन्हें बताया कि वास्तव में सतिंदर सेखों को मारने के लिए काला अम्ब बुलाया गया था।इस

परिस्थिति को यह स्थापित करने के लिए अपर्याप्त माना गया कि दर्शन सिंह साजिश का सदस्य था।"

32. उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद, दुर्भाग्य से खण्ड पीठ ने अपने पहले के निष्कर्षों पर एक परस्पर विरोधी निष्कर्ष निकाला और अचानक इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अपीलकर्ता ने मृतक को खत्म करने के लिए ए-1 से ए-4 के साथ साजिश रची। डिवीजन बेंच द्वारा निम्नलिखित निष्कर्ष बताए गए हैं:

"क्या यह कहा जा सकता है कि निर्मल सिंह के बारे में जो सच है वह बलकार सिंह चुडियाला के बारे में भी सच था। यह आरोपी वह व्यक्ति था जिसने हमलावरों को बंदूक और कार प्रदान की थी। वह आत्मसमर्पण करने से पहले 10 दिनों तक छिपने के लिए घटना के बाद भाग गया था।यह कहा जा सकता है कि बलकार सिंह चुडियाला भी फरार था क्योंकि वह जानता था कि उसे अपने दोस्त की हत्या के साजिशकर्ता के रूप में नामित किया जाएगा। निर्मल सिंह की तुलना में बलकार सिंह चुडियाला पर अधिक दांव था।उत्तरार्द्ध एक मंत्री था और राजनीतिक शक्ति और संरक्षण का आनंद लेता था, जबकि पूर्व केवल एक हैंगर-ऑन था, एक ऐसा व्यक्ति जो सतिंदर सेखों या अपने पेट्रोल पंप से कोई लाभ प्राप्त करने में असमर्थ था। निर्मल सिंह को राजनीतिक सत्ता मिली थी, सतिंदर सेखों को पेट्रोल पंप मिला था जो वह चाहते थे लेकिन बलकार सिंह चुडियाला को कुछ नहीं मिला। इसलिए, बलकार सिंह चुडियाला का सतिंदर सेखों की हत्या कराने का मकसद मजबूत था।वास्तव में, न तो बलकार सिंह चुडियाला और न ही निर्मल सिंह ने कभी कोई अच्छा काम किया था, लेकिन कम से कम निर्मल सिंह ने सरकार में एक ऐसे पद से बरी कर दिया था

जिससे उन्हें धन अर्जित करने का पर्याप्त अवसर मिला था।बलकार सिंह चुडियाला एक असफल और ड्रॉप-आउट थे। बलकार सिंह चुडियाला का सतिंदर सेखों की हत्या की साजिश रचने का मकसद मजबूत और आश्वस्त करने वाला था।

कमलजीत सिंह उर्फ लाली के मामले में, यह आरोपी घटना के बाद केवल बलकार सिंह चुडियाला के साथ चला गया था, लेकिन सतिंदर सेखों के खिलाफ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी या द्वेष नहीं था। कमलजीत सिंह के मामले में जिस सवाल पर विचार किया जाना है, वह यह है कि क्या मुख्य आरोपी के साथ उसका जाना इस तरह के आचरण के बराबर होगा जो उसे एक साजिशकर्ता के रूप में फंसाता है।हमें नहीं लगता कि इस तरह का निष्कर्ष निकाला जा सकता है।"

33. इसलिए, हम पाते हैं कि 6 वीं, 19 वीं और 20 वीं परिस्थिति पर खण्ड पीठ के पहले के निष्कर्ष सही थे, क्योंकि यह मानने के लिए सबूतों की पूरी कमी थी कि अपीलकर्ता (ए-10) पीडब्लू-36 से कार और ए-9 से बंदूक प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार था।जहाँ तक ए-11 के साथ ए-10 के भागने का सवाल है, जो ए-11 पर लागू होता है, वह ए-10, अर्थात् अपीलकर्ता पर भी समान रूप से लागू होना चाहिए। अभियोजन पक्ष के अनुसार, ए-14 मुख्य साजिशकर्ता था क्योंकि वह वही था जिसने मृतक को खत्म करने के लिए एक बड़ी दुर्भावना विकसित की क्योंकि मृतक उसे पेट्रोलियम व्यवसाय में हिस्सा देने के लिए इच्छुक नहीं था। अंतिम निष्कर्ष निचली अदालत के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा उसके समक्ष रखे गए साक्ष्य के आधार पर निकाला गया था कि उक्त परिस्थिति स्थापित नहीं हुई थी।इसलिए, हम यह समझने में विफल हैं कि कैसे ए-10 अकेले इस आधार पर साजिश रचने और मृतक को मारने के लिए खड़ा हो सकता है कि ए-10, ए-14 और मृतक एक बार अच्छे दोस्त थे और जबकि अन्य दो समय के

साथ जीवन में अच्छी स्थिति में थे, ए-10 को ड्रॉप आउट पाया गया।वास्तव में अभियोजन ए-1 के अनुसार भी अपीलकर्ता का भतीजा अपीलकर्ता के बाजार की देखभाल कर रहा था और अपीलकर्ता स्वयं एक रसायन इंजीनियर था और उसका अपना व्यावसायिक उद्यम था।यदि ऐसा है, तो उच्च न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि अपीलकर्ता एक ड्रॉप आउट था, न्यायालय के समक्ष रखे गए साक्ष्य द्वारा पूरी तरह से असमर्थित था।एकमात्र अन्य परिस्थिति जिसे अपीलकर्ता के खिलाफ कम किया जा सकता है, वह एक मुकदमा था जिसे उसके द्वारा मृतक के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा के आदेश दायर किया गया था ताकि उसे पेट्रोलियम व्यवसाय चलाने से रोका जा सके।हमें डर है कि ऐसी एकल परिस्थिति पर भरोसा आदेशके, अपीलकर्ता को एक साजिश को अंजाम देने के लिए अभिनिर्धारित किया जा सकता है, जब अभियुक्त के खिलाफ लगाए गए विभिन्न अन्य परिस्थितियों का एक-दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं था ताकि यह अभिनिर्धारित किया जा सके कि एकमात्र परिकल्पना जो निकाली जा सकती है वह अपीलकर्ता का अपराध होगा।

34. जहाँ तक साजिश का संबंध था, इस बात का कोई विशिष्ट प्रमाण नहीं था कि सभी साजिशकर्ता कौन थे, साजिश कहाँ और कब रची गई थी, इस तरह की साजिश का विशिष्ट उद्देश्य क्या था और क्या यह मृतक के उन्मूलन से संबंधित था। दूसरे शब्दों में, षड्यंत्र के सिद्धांत का समर्थन करने के लिए बुनियादी अवयवों में या तो भौतिक साक्ष्य के रूप में या अन्यथा पूरी तरह से कमी थी। ए-10 या ए-14 के इशारे पर कथित साजिश के लिए किसी भी परिस्थिति की कोई प्रासंगिकता नहीं थी, जिसके खिलाफ दोनों अदालतों ने क्लीन चिट दे दी थी।यह बताने के लिए कुछ भी नहीं था कि ए-10 ने ए-1 से ए-4 के साथ साजिश रची थी।दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष का विशिष्ट मामला यह था कि ए-14 के कहने पर, मुख्य साजिशकर्ता, ए-10 ने योजना को

निष्पादित किया। जब ए-14 ने पूरे मामले में कोई भूमिका नहीं निभाई, तो साजिश के सिद्धांत के लिए अकेले ए-10 को पिन करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

35. यहां तक कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के निष्कर्षों के अनुसार, ए5 से ए9 और ए11 से ए14 के खिलाफ लगाए गए साजिश के आरोप को खारिज कर दिया गया था। फिर यह ए1 से ए4 और ए10 के खिलाफ बना रहा। यहां तक कि काला अम्ब में कथित रूप से पहले की गई साजिश को भी स्थापित नहीं किया गया था।जहां तक ए1 से ए4 और ए10 का संबंध है, उन्हें साजिश के किसी भी कार्य, जगह, समय और साजिश की प्रकृति से जोड़ने के लिए कोई सबूत नहीं था। इसलिए, एक बार जब ए10 के खिलाफ भा.दं.सं. सी. की खंड 120बी के तहत साजिश के आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया, तो हम यह समझने में विफल रहते हैं कि कैसे अकेले उस पर आरोप लगाया जा सकता है और उस आरोप का दोषी पाया जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप भा.दं.सं. सी. की खंड 34 के साथ खंड 302 के तहत आरोप लगाया जा सकता है।

36. हमारे उपरोक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, हम आश्वस्त हैं कि अपीलकर्ता के खिलाफ भा.दं.सं. सी. की खंड 120बी के तहत लगाए गए साजिश के आरोप और भा.दं.सं. सी. की खंड 34 के साथ पठित खंड 302 के तहत आगे के आरोप निर्णायक रूप से साबित नहीं हुए थे और परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता पर लगाए गए दोषसिद्धि और सजा को कायम नहीं रखा जा सकता है। इसलिए, अपील स्वीकार की जाती है। अपीलकर्ता पर लगाए गए दोषसिद्धि और सजा को दरकिनार कर दिया जाता है।

बिभूति भूषण बोस अपील मंजूर की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।